

केंद्र के खिलाफ राज्यों की बढ़ती अपील से सर्वोच्च न्यायालय चतिति

प्रलिस के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष \(NDRF\)](#), [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#), [राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष](#)

मेन्स के लयि:

आपदा प्रबंधन, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, राज्य उधार लेने की शक्ति, केंद्र-राज्य संबंध

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्योँ?

[भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने राज्यों द्वारा केंद्र के खिलाफ उसके पास जाने के लयि **मजबूर होने की बढ़ती प्रवृत्त** पर चति व्यक्त की है।

कनि मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी?

■ तमलिनाडु:

- तमलिनाडु ने केंद्र पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए की आपदा राहत नधिमें देरी करके राज्य की जूरतों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

■ केरल:

- केरल ने सीधे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर कयि, जसिमें केंद्र पर उसकी 'नेट बॉरोइंग सीलगि' (2023-24 के लयि अनुमानति [सकल राज्य घरेलू उत्पाद](#) के 3% के रूप में नरिधारति) में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया, जसिसे राज्य [कोवतितीय आपातकाल](#) की ओर अग्रसर कर दयि गया।

■ कर्नाटक:

- मानवीय संकट से नपिटने के लयि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund- NDRF) के तहत कर्नाटक का ₹18,171.44 करोड़ का अनुरोध छह महीने से अनुत्तरति है।
- राज्य का तर्क है कि केंद्र की नषिक्रयिता न केवल [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#) के वैधानकि प्रावधानों का उल्लंघन करती है, बल्कि [भारत के संवधान](#) के तहत गारंटीकृत राज्य के लोगों के [मौलिक अधिकारों](#) का भी उल्लंघन करती है, जसिमें [समानता और जीवन का अधिकार](#) भी शामिल है।
 - राज्य गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है, जसिसे वर्षा में भारी कमी हो रही है, जसिसे लोगों का जीवन प्रभावति हो रहा है।

राज्यों द्वारा राजस्व उधार लेने और केंद्र के साथ वविाद नपिटारे हेतु संवैधानकि प्रावधान क्या हैं?

■ अनुच्छेद 293:

- इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन, कसिी राज्य की कार्यकारी शक्ति, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की संचति नधिकी सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदकि कोई हो, ऋण लेने तक वसितारति है, जो समय-समय पर वधियकि द्वारा तय की जा सकती है।
- भारत सरकार संसद द्वारा नरिधारति शर्तों के अधीन राज्यों को ऋण दे सकती है या गारंटी प्रदान कर सकती है।
- यदकि भारत सरकार के पछिले ऋण का कोई हसिसा बकाया रहता है तो **राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना ऋण नहीं उठा सकते हैं**।
 - यदकि आवश्यक हो तो भारत सरकार द्वारा शर्तों के साथ उधार लेने की सहमति दी जा सकती है।

■ अनुच्छेद 131:

- यह [सर्वोच्च न्यायालय](#) के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधति है। इसका मतलब यह है कि यह [सर्वोच्च न्यायालय](#) को नमिनलखिति के बीच वविादों को सीधे सुनने और नरिणय लेने का अधिकार देता है:

- केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारें ।
- दो या दो से अधिक राज्य सरकारें ।
- अनविर्य रूप से यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच या स्वयं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच असहमतियों में रेफरी/नरिणायक के रूप में कार्य करता है ।

| अवस्था | संवैधानिक प्रावधान | परमुख वशिषताएँ |
|-----------------|---------------------|---|
| वधायी संबंध | अनुच्छेद 245 से 255 | <ul style="list-style-type: none"> ■ संसद के पास राज्य वधिानमंडलों के लयि अत्यधिक वधायी शक्तयिँ होती हैं । ■ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वशिषयों की रूपरेखा । ■ सूचयिँ में शामिल नहीं कयि गए कसि भी वशिषय पर कानून बनाने का संसद का वशिष अधिकार । |
| प्रशासनिक संबंध | अनुच्छेद 256 से 263 | <ul style="list-style-type: none"> ■ राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना आवश्यक है । ■ प्रशासनिक मामलों में "सहकारी संघवाद" की अवधारणा । ■ कुछ मामलों पर राज्यों को नरिदेश देने की केंद्र की शक्ति । |
| वत्तीय संबंध | अनुच्छेद 264 से 293 | <ul style="list-style-type: none"> ■ केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तयिँ का वभिजन । ■ कर लगाने और उसके वभिजन के नियम । ■ राज्यों को वत्तीय अनुदान और संसाधन अंतरण के प्रावधान । |

राज्यों के लयि आपदा बहाली योजनाओं में केंद्र सरकार की क्या भूमिका है?

- **आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005:**
 - आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 आपदा प्रबंधन के लयि राष्ट्रिय, राज्य, ज़िला और स्थानीय स्तर पर संस्थागत, कानूनी, वत्तीय एवं समन्वय तंत्र नरिधारति करता है ।
 - यह अधनियम आपदा प्रबंधन प्रयासों की देखरेख और कार्यान्वयन के लयि **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** एवं राज्य तथा ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे विभिन्न प्राधिकरणों व समतियिँ की स्थापना को अनविर्य करता है ।
 - यह अधनियम **केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन में सुवधि या सहायता के लयि NDMA, राज्य सरकारों/SDMA**, या उनके कसि भी अधिकारी/कर्मचारी को नरिदेश जारी करने का अधिकार देता है ।
 - **वत्ति आयोग** आपदा प्रतिक्रिया के साथ-साथ आपदा शमन के लयि धन के नरिमाण की सफिराशि करता है, जसि अब एक **साथराष्ट्रीय आपदा जोखमि प्रबंधन कोष (NDRMF) और राज्य आपदा जोखमि प्रबंधन कोष (SDRMF)** कहा जाएगा ।
 - 15वें वत्ति आयोग ने वर्ष 2021-26 की अवधि के लयि **राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF)** की सफिराशि की, तथा NDMF के साथ-साथ **राज्य DMF** की स्थापना की गई है ।
 - SDRMF में केंद्र व राज्य दोनों सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है, **सामान्य राज्यों के लयि 75:25 अनुपात और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लयि 90:10 अनुपात** नरिधारति होता है ।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF):**
 - आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के तहत गठति **SDRF**, अधसूचति आपदाओं की प्रतिक्रिया के लयि राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक नधि है ।
 - **केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के लयि SDRF आवंटन का 75%** तथा वशिष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों, सकिक्मि, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर) के लयि 90% का योगदान करती है ।
 - वत्ति आयोग की सफिराशि के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान कशितों में जारी कयि जाता है ।
 - SDRF का उपयोग केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के वयय को पूरा करने के लयि कयि जाएगा ।
 - **SDRF के अंतरगत आने वाली आपदाएँ: चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूसखलन, हिमसखलन, बादल फटना, कीट हमला, ठंड और ठंडी लहरें ।**
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF):**
 - आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 की धारा 46 के तहत स्थापति NDRF, खतरनाक स्थतियिँ या आपदाओं के दौरान आपातकालीन

प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास को संबोधित करने के लिये **केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक कोष** है।

- यह गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में राज्य के SDRF को पूरक बनाता है, बशर्ते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।
- इस कोष को भारत सरकार के "सार्वजनिक खाते" में "ब्याज न देने वाली आरक्षण कोष" के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे सरकार इसे संसदीय अनुमोदन के बिना उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
- NDRF को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अधीन वशिष्ट वस्तुओं पर लगाए गए उपकर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे वित्त वधियक के माध्यम से वार्षिक तौर पर मंजूरी दी जाती है।
- NDRF आवंटन से परे अतिरिक्त कोषीय आवश्यकताओं को सामान्य बजटीय संसाधनों के माध्यम से पूरण किया जाता है, जिससे आपदा राहत प्रयासों के लिये नरिंतर समर्थन सुनिश्चित होता है।
- कोष के उपयोग की नगिरानी NDMA की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) द्वारा की जाती है, जिसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा वार्षिक ऑडिट किया जाता है।

वित्तीय सहायता के वितरण के संबंध में राज्यों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

■ वलिंबति एवं अपर्याप्त आपदा राहत:

- आपदा प्रबंधन नधि (NDRF तथा SDRF) के वितरण में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का अभाव।
 - आपदा सहायता की मात्रा नरिधारित करने में **केंद्र के एकतरफा नरिणय लेने पर चिता**।
- राज्यों को आपदा राहत एवं पुनर्वास सहायता की मात्रा नरिधारित करने के लिये केंद्र के पास **पासस्पष्ट, पारदर्शी और उद्देश्यपूरण मानदंडों का अभाव**।
- आपदा सहायता पर केंद्र के नरिणयों को चुनौती देने के लिये राज्यों के पास पर्याप्त संस्थागत तंत्र का अभाव।

■ केंद्र-राज्य आपदा प्रबंधन ढाँचे में असंतुलन:

- आपदा प्रबंधन शक्तियों एवं नरिणय लेने के अधिकार के संदर्भ में केंद्र के पास अति-केंद्रीकरण।
- NDMA के केंद्र पर अत्यधिक नरिभर होने तथा **राज्यों के प्रभावी प्रतनिधित्व की कमी को लेकर चिताएँ हैं**।
- राज्यों के पास अपने स्थानीय संदर्भों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार, आपदा प्रतिक्रिया तथा शमन उपायों को अनुकूलित करने हेतु लचीलेपन का अभाव है।

■ केंद्रीकृत योजना:

- केंद्रीकृत योजना हमेशा प्रत्येक राज्य की वशिष्ट आवश्यकताओं तथा परस्थितियों को ध्यान में नहीं रख सकती है, जिससे आपदाओं अथवा सहायता की आवश्यकता वाली अन्य स्थितियों की प्रतिक्रिया में अक्षमताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

■ राजनीतिक गतशीलता:

- केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच राजनीतिक गतशीलता एवं संबंधों में सहायता वितरण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कभी-कभी पूराग्रह अथवा पक्षपात के आरोप भी लग सकते हैं।

■ परामर्श का अभाव:

- केंद्र पर प्रायः नीतियों तथा योजनाओं को तैयार करते समय राज्यों से परामर्श नहीं करने का आरोप लगाया जाता है, जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- केंद्र द्वारा राज्यों की सहमतिकाे बिना उन पर एकतरफा नरिणय थोपना भी उदाहरण टकराव का एक स्रोत रहे हैं।
- केंद्र और राज्यों के बीच नयिमति संवाद एवं विवाद समाधान हेतु प्रभावी संस्थागत मंचों का अभाव।
- बढ़ती प्रतस्पर्द्धात्मक एवं प्रतकूल राजनीति के सामने संघीय भावना तथा सहयोगात्मक दृष्टिकोण का कमजोर होना।

आगे की राह

- कराधान शक्तियों एवं राजस्व बँटवारे की समीक्षा करके, राजकोषीय असंतुलन को दूर करके **राजकोषीय संघवाद** को बढ़ावा देना।
- केंद्र और राज्यों के बीच **नयिमति संवाद एवं आम सहमतिकाे बनाने के लिये संस्थागत मंचों को पुनर्जीवित** करना। केंद्र-राज्य विवादों को संबोधित करने हेतु सहयोगात्मक नीति नरिधारण तथा प्रभावी विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना।
- आपदा राहत नधि एवं सहायता उपयोग हेतु नरिणय लेने में **पारदर्शिता में सुधार** करना। नधि के गबन तथा भेदभाव को रोकने के लिये **लेखापरीक्षा एवं नरिीक्षण बढ़ाना**।
- एक ऐसी **राजनीतिक संस्कृतिकाे बढ़ावा देना जो पक्षपातपूरण एजेंडे पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता** देती है तथा केंद्र और राज्य स्तरों के बीच सहयोग एवं पारस्परिक सम्मान बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। प्रभावी शासन तथा न्यायसंगत विकास के लिये सहकारी संघवाद के महत्त्व के बारे में नागरिकों को शक्ति करती है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. राजनीतिक गतशीलता एवं अपर्याप्त परामर्श संकट के समय केंद्र-राज्य को सहयोग करने से कैसे रोकते हैं, और अधिक सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिये क्या बदलाव किये जाने चाहिये?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धतकी वशिषता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है ।
- (b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वभिजन कया गया है ।
- (c) संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतनिधितिव दया गया है ।
- (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमतिका परणाम है ।

उत्तर: (d)

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कथिह एक प्रयोग है: (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
- (c) प्रशासनिक प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. पहले के प्रतक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु शुरू कयि गए हालया उपायों की चर्चा कीजयि । (2020)

प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण (NDMA) के दशा-नरिदेशों के संदर्भ में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लयि अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजयि । (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/sc-ocnered-by-growing-states-appeals-against-centre>

